"केवल राइट (अधिकार) ही रौंग (गलत) को रोक सकते हैं"

यौन कार्य को नियंत्रित करने वाले कानूनों के दूरगामी प्रभाव

दुनियाभर में यौन कार्य को नियंत्रित करने के लिये कई तरह के कानूनी मॉडल हैं। कुछ देशों में ऐसे कानून हैं जो यौन कर्मियों के अधिकारों का सम्मान करते हैं, अन्य देशों में विभिन्न स्तर के दंडात्मक, दमनकारी कानून हैं जो यौन कर्मियों, उनके परिवारों और बड़े पैमाने पर समाज के लिये विनाशकारी परिणाम लाते हैं। दुर्भाग्य से, दुनिया के अधिकांश देशों का दृष्टिकोण इसी प्रकार से नकारात्मक है।

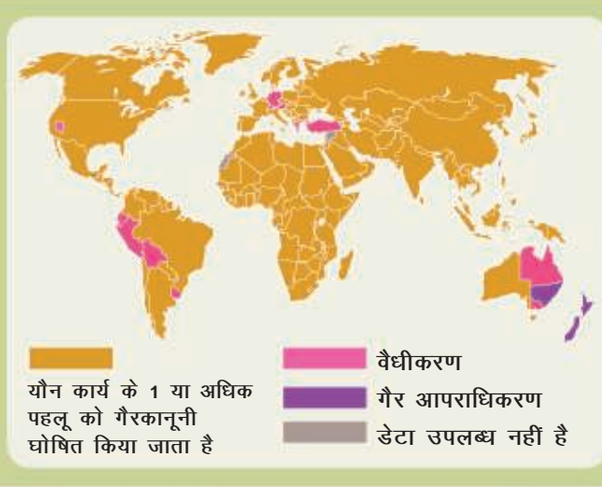

यौन कार्य के विभिन्न कानूनी मॉडल

		उदाहरण
1 पूर्ण अपराधीकरण	सेक्स बेचने और खरीदने या यौन कार्य आयोजित करने के सभी पहलू निषिद्ध हैं।	दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका
2 आंशिक अपराधीकरण	यौन कार्य का आयोजन निषिद्ध है, जिसमे दूसरों के साथ काम करना, वेश्यालय चलाना, तीसरे पक्ष की भागीदारी* या यौन संबंधों के लिये आग्रह करना शामिल है।	भारत, यूनाइटेड किंगडम (उत्तरी आयरलैंड को छोड़कर)
3 सेक्स की खरीद का अपराधीकरण	कानून यौन कर्मियों को एक साथ काम करने (तीसरे पक्ष के कानूनों के तहत), तीसरे पक्ष के रूप में देह व्यापार में भाग लेने के किसी भी पहलू, और सेक्स की खरीद को दंडित करता है। इसे सेक्स–खरीदार मॉडल, एंड डिमांड मॉडल, या नॉर्डिक मॉडल के रूप में भी जाना जाता है।	स्वीडन, सर्बिया
4 नियामक मॉडल	सेक्स की बिक्री लाइसेंस प्राप्त मॉडल और/या प्रबंधित क्षेत्रों में कानूनी है और अक्सर अनिवार्य कंडोम उपयोग, एचआईवी/एसटीआई परीक्षण, या पंजीकरण के साथ होती है।	नीदरलैंड, मेक्सिको
5 पूर्ण गैर–अपराधीकरण	वयस्क यौन कार्य के सभी पहलुओं को गैर आपराधिक कर दिया गया है, लेकिन कुछ स्थानों पर कंडोम का उपयोग कानूनी रूप से आवश्यक है।	न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के कुछ राज्य

"प्लेट्ट और अन्य (2018) से अनुकूलित तालिका
"तीसरा पक्ष वह है जो यौन कार्य को संचालित करता है (जैसे वेश्यालय के मालिक, मैनेजर, मकानमालिक आदि)।

अपराधीकरण का खतरा

दुनिया के ज्यादातर देश यौन कार्य के किसी न किसी पहलू को अपराध मानते हैं। इन मामलों में, कानून का उपयोग आपराधिक कानून, स्थानीय नियमों और कानून प्रवर्तन की दंडात्मक प्रथाओं के माध्यम से यौन कर्मियों पर अत्याचार करने के लिये किया जाता है।

यौन कार्य के किसी भी पहलू को अपराध घोषित करने के परिणामः

- **यौन कर्मियों को अपराधियों में बदल देता है,** और उन्हें कई तरह के अपमान, दंड, उत्पीड़न, जबरन वसूली का विषय बना देता है, और उनके अधिकारों को सीमित कर देता है। इससे यौन कर्मियों में अधिकारियों के प्रति डर बढ़ जाता है, जिसका अर्थ है कि यौन कर्मियों द्वारा अपराधों की रिपोर्ट करने, समर्थन मांगने या सेवाओं तक पहुँचने की संभावना कम होती है।
- **यौन कर्मियों को कानून का संरक्षण प्राप्त नहीं है।** उदाहरण के लिये, यौन कर्मी जो अधिकारियों को बलात्कार की रिपोर्ट करना चाहते हैं, उन्हें अक्सर इस मान्यता के कारण मना कर दिया जाता है कि यौन कर्मियों का बलात्कार नहीं किया जा सकता है, या फिर वे सामाजिक सेवाओं या न्याय के लायक नहीं हैं।
- **यौन कार्य से जुड़े सामाजिक कलंक को मज़बूत करता है** और लोगों के पूर्वाग्रहों, यौन कर्मियों और उनके ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार और भेदभावपूर्ण व्यवहार को वैध बनाता है।
- **यौन कर्मियों को एक आपराधिक रिकॉर्ड के साथ छोड़ देता है** जो उन्हें अन्य रोजगार के अवसरों या सेवाओं तक पहुँचने से रोकता है।
- **यौन कर्मियों को कामगारों की सुरक्षा के लिये बनाये गये कानूनों से बाहर रखा जाता है** – जैसे कि व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा कानून, श्रम कानून, और बेरोजगारी लाभ, क्योंकि यौन कार्य को कार्य का एक रूप नहीं माना जाता है।
- **यौन कार्य को असुरक्षित बनाता है** क्योंकि कानून प्रवर्तन द्वारा "कंडोम को यौन कार्य के सबूत" के रूप में मानने का मतलब है कि यौन कर्मी और उनके ग्राहकों द्वारा कंडोम ले जाने की कम संभावना होती है, जिससे एसटीआई (एचआईवी सहित) और खराब स्वास्थ्य का खतरा बढ़ जाता है।

"अपराधीकरण, ग्राहकों और तीसरे पक्षों सहित, यौन कर्मियों पर पुलिस दमन को बढ़ाता है, सेवाओं तक पहुँचने में यौन कर्मियों के खिलाफ भेदभाव होने देता है, और सभी प्रकार के सामाजिक कलंक को हवा देता है। इससे यौन कर्मियों को गंभीर नुकसान होता है, जिसमें हिंसा के अनुभव और न्याय तक पहुँचने में बाधाएं शामिल हैं।" "ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्क प्रोजेक्ट्स

क्या "एंड डिमांड" मॉडल यौन कार्य को सुरक्षित बनाता है?

ऐसे कानूनों के समर्थक जो ग्राहकों, मैनेजरों और वेश्यालय के मालिकों को आपराधिक मानते हैं, लेकिन यौन कर्मियों को नहीं, उनका मानना है कि यह मॉडल यौन कर्मियों को हिंसा से बचाकर उनकी मदद करता है, और सेक्स की बिक्री की सुविधा देकर, महिलाओं का शोषण करने वालों को दंडित करता है। हालाँकि, रिसर्च से पता चलता है कि किसी भी प्रकार का अपराधीकरण यौन कार्य को असुरक्षित बनाता है और यौन कर्मियों के लिये इसके खराब परिणाम होते हैं। यहाँ तक कि आंशिक अपराधीकरण – "एंड डिमांड" मॉडल की तरह – पूर्ण अपराधीकरण के तहत देखे गये नुकसान को दोहराता है और यौन कर्मियों को हिंसा और एचआईवी संक्रमण के प्रति संवेदनशील बनाता है। यह मॉडल यौन कार्य और तस्करी के मिश्रण को प्रोत्साहित करता है, यह सुझाव देते हुए कि सभी यौन कार्य महिलाओं के विरुद्ध हिंसा है, और इस प्रकार यौन कार्य से जुड़े सामाजिक कलंक को बढ़ाता है।

"वे इसे कम सुरक्षित बनाने के लिये इससे बेहतर कानून नहीं बना सकते थे, भले ही वे सालों तक बैठते! ("एंड डिमांड" मॉडल के तहत) ऐसा लगता है कि आपको छिपना है, आप एक आदमी से बात नहीं कर सकते हैं, और इस बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं कि आप क्या करने को तैयार हैं और कितने के लिये। बातचीत बाद में होनी होती है, जो हमेशा बहुत डरावनी होती है" – महिला यौन कर्मी, कनाडा

यौन कर्मियों के लिये हानिकारक अन्य कानून

कुछ देशों में यौन कार्य को स्पष्ट रूप से अपराध नहीं माना जाता है या यौन कर्मी एक "नियमविहीन क्षेत्र" में काम करते हैं। अक्सर इन परिस्थितियों में, कानून प्रवर्तन अधिकारी आपराधिक कानून से परे अन्य कानूनों और नीतियों के माध्यम से यौन कर्मियों को निशाना बनाते हैं और दंडित करते हैं। ये कानून यौन कर्मियों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, ऐसे कानूनों के उदाहरणों में निम्न शामिल हैं:

सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून जो यौन कर्मियों के लिये एसटीआई के लिये परीक्षण करना, या अधिकारियों के साथ पंजीकरण अनिवार्य करते हैं। इस तरह के कानून यौन कर्मियों के मानव अधिकारों को खतरे में डालते हैं, विशेष रूप से गोपनीयता और शारीरिक स्वायत्तता के उनके अधिकार और बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासी यौन कर्मियों के लिये स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को कम करते हैं।

सार्वजनिक नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था कानून जो "आवारगी", "आवारा फिरना", और असामाजिक व्यवहार" या "अभद्रता" पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यौन कर्मियों को परेशान करने और दंडित करने के लिये उपयोग किये जाते हैं।

पारंपरिक, प्रथागत और धार्मिक कानून जिनमें व्यभिचार या समलैंगिक संबंधों के खिलाफ व्यापक और दंडात्मक निषेध शामिल हैं जो यौन कर्मियों पर प्रयोग किये जाते हैं।

प्रवासन कानून जो लोगों की गतिशीलता, आवाजाही और आजीविका रणनीतियों को विनियमित करते हैं और प्रवासी यौन कर्मियों को नियंत्रित और लक्षित करने के लिये उपयोग किये जाते हैं।

समलैंगिकता संबंधी कानून जो गे, लेस्बियन, बाईसेक्शुअल और ट्रांसजेंडर समुदाय को लक्षित करते हैं। ये कानून यौन अभिविन्यास और जेंडर पहचान के आधार पर भेदभाव करते हैं और जेंडर की धारणा में न बंधने वाले यौन कर्मियों पर इनका प्रभाव पड़ता है।

पुराने अंतरराष्ट्रीय कानून जैसे "व्यक्तियों में तस्करी के दमन और दूसरों की वेश्यावृत्ति के शोषण के लिये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन" (1949) और 'महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन' (1979) में अस्पष्ट शब्द, जो कि यौन कर्मियों के अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा यह तर्क देने के लिये उपयोग किये जाते हैं कि यौन कार्य को आपराधिक बनाये रखना चाहिए।

सामाजिक न्याय के लिये एक उपकरण के रूप में कानून: यौन कार्य को गैर आपराधिक करार देना

कानून में पिछले नुकसान को दूर करने, हाशिए के समूहों की गरिमा की पुष्टि करने और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को उत्प्रेरित करने की क्षमता है। यौन कार्य के संबंध में सामाजिक न्याय लाने के लिये यह आवश्यक है कि यौन कार्य को कार्य के रूप में माना जाये और कानूनी रूप से इसे मान्यता दी जाये। इसका मतलब है कि यौन कार्य को मंजूरी देने या यौन कर्मियों को दंडित करने के लिये उपयोग किये जाने वाले नागरिक और आपराधिक कानूनों को निरस्त करना और यौन कार्य को उपयुक्त श्रम ढांचे के तहत लाना है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि यौन कार्य को अधिकार–आधारित तरीके से किया जा रहा है। यह यौन कार्य के संदर्भ को सुरक्षित बनाता है और सेक्स वर्कर्स की गरिमा और अधिकारों की पुष्टि करते हुए सेवाओं तक पहुँच और कानून की सुरक्षा को बढ़ाता है।

गैर अपराधीकरण की परिभाषा:

*"कुछ यौन कर्मी समूह **आपराधिक कानूनों की अनुपस्थिति का उल्लेख** करने के लिये गैर अपराधीकरण का उपयोग करते हैं जो स्वयं यौन कार्य या वेश्यालय चलाने जैसी संबंधित गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं। अन्य समूह पूर्ण गैर अपराधीकरण का उल्लेख **सुधार की एक विस्तृत श्रृंखला** के हिस्से के रूप में करते हैं, जो अपराध–विरोधी रणनीति के हिस्से के रूप में यौन कर्मियों और अन्य हाशिए के समुदायों के अधिकारों को साकार करने के लिये आवश्यक हैं। इनमें सभी कानूनी उत्पीड़नों को हटाना शामिल है – न कि केवल आपराधिक कानूनों को। यह इस तथ्य को उजागर करता है कि यौन कार्य–विशिष्ट आपराधिक कानूनों की अनुपस्थिति में यौन कर्मियों, ग्राहकों, तीसरे पक्षों, परिवारों, भागीदारों और दोस्तों को अभी भी अन्य प्रकार के कानूनों द्वारा अपराधी बनाया जाता है। उदाहरणों में शामिल हैं आवारापन, सार्वजनिक उपद्रव, अश्लीलता, नशीले पदार्थों के उपयोग के खिलाफ कानून या समलैंगिकता या क्रॉस–ड्रेसिंग के खिलाफ कानून। पुलिस और अन्य सरकारी अधिकारी यौन कर्मियों को असमान रूप से लक्षित करने के लिये इन कानूनों का उपयोग करना जारी रखेंगे।" ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्क प्रोजेक्ट्स*

सन्दर्भ: *Asijiki (2015). "Sex work and the Law: Four possible legal options". Asijiki Fact Sheet.; Global Network of Sex Work Projects (2018) "Rights-Affirming International Policies Relating to Sex Work - The Smart Sex Worker's Guide"; Global Network of Sex Work Projects (2017) "The Impact of Criminalisation on Sex Workers' Vulnerability to HIV and Violence A Community Guide"; Global Network of Sex Work Projects (2017) "Sex Work as Work" Community Guide; Global Network of Sex Work Projects (2014) Briefing Paper#07 "Sex Work And The Law: Understanding Legal Frameworks and the Struggle for Sex Work Law Reforms"; A Krüsi et al (2014) "Criminalisation of Clients: Reproducing Vulnerabilities for Violence and Poor Health among Street-Based Sex Workers in Canada—A Qualitative Study" British Medical Journal Open 4(6); Platt, Lucy et al (2018). "Associations between sex work laws and sex workers' health: A systematic review and meta-analysis of quantitative and qualitative studies". PLoS Medicine 15(12); The Sex Workers' Rights Advocacy Network (SWAN) (2019) "Sex Work Legal Frameworks in Central-Eastern Europe and Central Asia".*